

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थागण एवं प्रत्यर्था विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	779/2017 डॉ. उम्मेद सिंह मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	08.05.2017	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं प्रत्यर्था विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2.	781/2017 डॉ. रवि कुमार गुप्ता	2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन, कोटा।		
3.	783/2017 डॉ. शरद पररुथी	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन, कोटा। 3. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, बारां।		
4.	822/2017 डॉ. हेमन्त गुप्ता	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था संख्या 1 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन, कोटा।	19.05.2017	

आदेश की दिनांक : 07.10.2024

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 779/2017 डॉ. उम्मेद सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2016 एवं 15.02.2017 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय डीएसीपी का लाभ दिनांक 11.07.2011 एवं 11.07.2013 से प्राप्त करने का अधिकारी है और अपीलार्थी से प्रत्यर्था विभाग उक्त संबंध में कोई वसूली न करे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 20.06.1996 को हुई थी और उसे संशोधित नियम दिनांक 08.02.2013 के अनुसार डीएसीपी का लाभ आवश्यक सेवा अनुभव पूर्ण होने पर दिया गया है, जो दिनांक 11.04.2011 से दिया गया है। अपीलार्थी को ग्रेड पे 7600 आदेश दिनांक 27.02.2016 के द्वारा प्रदान किया गया, जो दिनांक 11.07.2011 से निर्धारित किया गया और दिनांक 11.07.2011 से 27.02.2016 तक की शेष राशि का भुगतान अपीलार्थी को किया गया। उनका कथन है कि माननीय राज्यपाल द्वारा एवं वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.08.2011 एवं 10.07.2012 डीएसीपी का लाभ दिये जाने का आदेश जारी किया गया और उक्त लाभ आवश्यक सेवा अनुभव पूर्ण होने पर ही प्रदान किया जाता है और इस प्रकार अपीलार्थी को ग्रेड पे 7600 का लाभ दिनांक 11.07.2011 से दिया गया एवं ग्रेड पे 8700 का लाभ दिनांक 11.07.2013 के बजाय दिनांक 01.04.2016 से दिया गया। जबकि उनका कथन है कि निदेशक द्वारा जो आदेश दिनांक 05.10.2016 जारी किया गया है, जिसमें पदोन्नत कार्मिकों को रिक्ति दिनांक से काल्पनिक लाभ एवं कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ दिये जाने का उल्लेख है और इस प्रकार अपीलार्थी को दिया गया लाभ बिना किसी नोटिस के प्रत्याहृत नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2016 एवं 15.02.2017 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय डीएसीपी का लाभ दिनांक 11.07.2011 एवं 11.07.2013 से प्राप्त करने का अधिकारी है और अपीलार्थी से प्रत्यर्थी विभाग उक्त संबंध में कोई वसूली न करे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत आदेश दिनांक 04.01.2016 द्वारा अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 11.07.2011 से उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर ग्रेड पे 7600 पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिस पर नियम 1963 एवं डीपीसी नियमानुसार पदोन्नति की तिथी से काल्पनिक लाभ एवं पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथी से नकद लाभ देय है। यदि इन नियमों के विपरीत नकद भुगतान किया गया है तो वसूली योग्य है। वित्त विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत कार्मिकों को रिक्ति दिनांक से काल्पनिक लाभ एवं कार्यग्रहण की

दिनांक से नकद लाभ दिये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 30.07.2013 जारी किया गया है तथा पूर्ववर्ती वर्ष की डीएसीपी के तहत पदोन्नति होने की दिनांक से काल्पनिक लाभ एवं पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा और इस प्रकार चिकित्साधिकारियों की समय-समय पर होने वाली पदोन्नति के बाद जारी आदेशों से पदोन्नति पद पर उपस्थिति दिनांक के बजाय पदोन्नति तिथि से शेष राशि का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, जो नियमानुसार गलत है और इस प्रकार वसूली किया जाना नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 20.06.1996 को हुई थी। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002-03 के विरुद्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2006 में पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा शिक्षक की पदोन्नति दिये जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 के अंतर्गत डीएसीपी स्कीम बनाई गई, जिसमें आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार दिनांक 08.02.2013 को उप निदेशक एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर ग्रेड पे 7600 दिया जाना उचित बताया है, जिनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो या उससे अधिक, को वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.08.2011 के अनुसार एसएसएमओ मय दंत/उप सीएमएचओ/कनिष्ठ विशेषज्ञ जिनकी ग्रेड पे 6600 हो, दिनांक 11.07.2011 को उप निदेशक, सीएमएचओ एवं समकक्ष पद/वरिष्ठ विशेषज्ञ ग्रेड पे 7600 पर पदोन्नति योग्य होंगे और इस प्रकार अपीलार्थी ग्रेड पे 7600 में निर्धारित किया गया। जहां तक आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी से वसूली किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.02.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24बी एवं 24बीबी(5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 11.07.2011 से प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ग्रेड

पे 7600 में पदोन्नत किया गया और उक्त पदोन्नति नियमों एवं प्रावधानानुसार की गई है। डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्त विभाग के परामर्श अनुसार दिनांक 11.07.2011 को डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पश्चात् 2 वर्ष की राज सेवा दिनांक 11.07.2013 को अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया गया है और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 जारी की गई, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया :-

"The Medical Officer including Dental who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have been promoted under Finance Department Memorandum dated 09.08.2011 on the post of Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Junior Specialist in grade pay of Rs. 6600/- as on 11.07.2011, shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Senior Specialist in grade pay of Rs. 7600/- after completion of service of two years instead of 6 years in the grade pay of Rs. 6600/-. The third DACP in grade pay of Rs. 8700/- shall be admissible on completion of service of four years instead of 6 years in the grade pay of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts."

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

"The Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Junior Specialist who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per provisions of the relevant recruitment rules and have also completed at least 6 years service in GP of Rs. 6600/- or in the corresponding existing pay scale as on 11.07.2011 and have been promoted under Memorandum of even number dated 09.08.2011 on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Senior Specialist in GP of Rs. 7600/- as on 11.07.2011 shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical Officer/Additional Director and equivalent posts/Principal Specialist in the GP of Rs. 8700/- after completion of service of 2 years instead of 6 years in GP of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.

(ii) the existing word and figure "maximum 5%" appearing in remarks column against S.No. 4 shall be substituted by the word and figure "maximum 18%".

This order shall come into force w.e.f. 11.07.2011. The above Time Bound Promotions shall be admissible only after necessary amendments in the relevant service rules to this effect."

इस प्रकार उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 के अनुसार ही अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के तहत 2 वर्ष पूर्ण होने पर लाभ दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं और आलोच्य आदेश दिनांक 15.02.2017 अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थीगण से वसूली नहीं की जावे। अधिकरण के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.05.2017 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 779/2017 डॉ. उम्मेद सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य